दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>निर्णय सुरक्षित: 13.02.2024</u>
<u>निर्णय उद्घघोषित: 10.05.2024</u>

<u>सि.वा.(मू.प.) 289/2022 और अं.आ. 7971/2022, अं.आ. 7972/2022, अं.आ. 7973/2022, अं.आ. 7974/2022, अं.आ. 7975/2022, अं.आ. 7976/2022, अं.आ. 9506/2022, अं.आ. 13967/2022, अं.आ. 19558/2022, अं.आ. 19559/2022, अं.आ. 16052/2023, अं.आ. 24643/2023, अं.आ. 24644/2023</u>

वन्दना बत्रा ..... वादी

द्वारा : श्री वाई. पी. नरूला, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री तारा नरूला, श्री एस. देबब्रत रेड्डी, श्री हर्षवर्धन जैन, श्री अनिरुद्ध रामनाथन, अधिवक्तागण

बनाम

अनुपम गुप्ता और अन्य ..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री मनीष वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री रिक्की गुप्ता, सुश्री अनन्या सिंह, सुश्री हर्षिता नाथकंज, श्री अमन सिंह, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय श्री न्यायमूर्ति जसमीत सिंह

<u>निर्णय</u>

: **न्या. जसमीत सिंह.**

अं.आ. 16426/2023

1. यह आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित बयान के संशोधन करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदेश VI नियम 17 के साथ पठित धारा 151 सि.प्र.स. के तहत अपने लिखित बयान के प्रारंभिक आपत्तियों के शीर्षक के तहत कुछ अतिरिक्त पैराग्राफ को शामिल करके संशोधन करने की मांग की गई है। प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं:-

> *"7. यह इस तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता ने दिनांकित 27.12.2019 की वसीयत को छोड़कर गुजर गए। हालांकि, अगर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता की उस स्थिति में निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है, तो निम्नलिखित अचल संपत्तियों को कानून के अनुसार वादी और प्रतिवादियों के बीच भी विभाजित किया जा सकता है।*
> *क. स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता ने अपने जीवनकाल में वादी और उसके परिवार के सदस्यों को कुल 5,23,49,700/- रुपये (पांच करोड़ तेईस लाख उनचास हजार सात सौ रुपये केवल) का भुगतान/हस्तांतरण किया, जिसमें उपरोक्त 1.6 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल थी जैसा ऊपर कहा गया था वादी को हस्तांतरित की गई राशि उसके बैंक खातों में जमा की गई थी (i) बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लिमिटेड (खाता संख्या 518518), (ii) हांगकांग और शंघाई बैंक निगम (खाता संख्या 003214442006), (iii) बैंक ऑफ इंडिया (खाता संख्या 8875693077)। स्वर्गीय श्री*

एम.एल.गुप्ता द्वारा अंतरित धन का उपयोग निम्नलिखित अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया गया है।

<u>ख. 141, टॉवर-ए, कल्पतरु होराइजन, एस.ए. अहीर मार्ग दूरदर्शन टॉवर के पास, वर्ली, मुंबई</u>

स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता ने बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी लिमिटेड पर दिनांक 12.04.2005 को चेक संख्या 932166 के माध्यम से वादी को 1.60 करोड़ रुपये का ऋण दिया और बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी लिमिटेड में वादी के बचत बैंक खाते संख्या 518518 में भुगतान किया। उक्त राशि वादी को उपरोक्त संपत्ति खरीदने के लिए दी गई थी। यह एक तथ्य है जो पूरे परिवार को पता है कि वादी ने उक्त राशि अपने पति को हस्तांतरित कर दी, जिन्होंने उक्त राशि का उपयोग करके उपरोक्त संपत्ति खरीदी। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वादी ने उक्त ऋण राशि स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता को कभी वापस नहीं की और यह अभी भी स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता की पुस्तकों में मौजूद है। यह लेन-देन वादी को 09.04.2005 को दिया गया ऋण था, जिसकी विधिवत घोषणा की गई थी और स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता के जीवनकाल के दौरान आयकर विभाग को इसकी पुष्टि की गई थी।

<u>ग. फ्लैट संख्या 402, अधिश्वर अपार्टमेंट, 34 फिरोज शाद रोड, नई दिल्ली-</u>

उपरोक्त संपत्ति स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता द्वारा 16.12.1998 को आयकर अधिकारियों द्वारा आयोजित नीलामी में खरीदी गई थी। स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता ने 1 करोड़ 15 लाख दस हजार रुपये की राशि का भुगतान किया। स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता ने दिनांक 16.12.1998 को 29 लाख 25 हजार रुपये की राशि निम्नलिखित तरीके से जमा की:

क्र. स.	चेक. स.	कुल धनराशि	दिनांकित	पर खींचा गया
1	040696	28,75,000/-	16.12.1998	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लिमिटेड
2	040697	25,000/-	16.12.1998	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लिमिटेड
3	040698	25,000/-	16.12.1998	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लिमिटेड
	कुल	29,25,000/-	(रुपये उनतीस लाख पच्चीस हज़ार केवल)	

85,85,000/- रुपये की शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता द्वारा 31.12.1999 को भुगतान आदेश संख्या 056379 द्वारा किया गया था। इस प्रकार श्री एम.एल.गुप्ता ने उक्त संपत्ति की पूरी बिक्री प्रतिफल का भुगतान कर दिया। उक्त संपत्ति का कब्जा हमेशा स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता के पास रहा और इसके बाद यह आवेदक/प्रतिवादी संख्या 1 के वास्तविक कब्जे में है।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि आज तक आयकर अधिकारियों ने उक्त संपत्ति का हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 के संज्ञान में यह आया है कि वादी प्रतिवादियों के बहिष्कार के लिए अपने

नाम पर उक्त संपत्ति का हस्तांतरण विलेख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

<u>घ. ई-8-ए प्रथम तल, हौज खास मेन मार्केट, नई दिल्ली।</u>

स्वर्गीय श्री एम. एल. गुप्ता ने एचडीएफसी बैंक चेक संख्या 255806 के माध्यम से वादी को 1,76,00,000/- रुपये (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) की राशि हस्तांतरित की थी। वादी ने इसके बाद उपरोक्त संपत्ति खरीदी और पिता स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने के बाद मार्च, 2009 में वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था और इसलिए, यह भी श्री एम.एल.गुप्ता द्वारा अपने स्वयं के धन से खरीदी गई संपत्ति में से एक है।

8. यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने जानबूझकर उपरोक्त संपत्तियों को वर्तमान वाद में शामिल नहीं किया है क्योंकि वह प्रतिवादियों के ऊपर गुप्त तरीके से फयदा उठाना चाहती थी। इस प्रकार वादी ने नेक नीयत से इस माननीय न्यायालय से संपर्क नहीं किया है।

9. यह प्रतिवादी संख्या 1 के ज्ञान में आया है कि वादी विभिन्न संपत्ति डीलरों से पूछताछ कर रही है और उपरोक्त संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी को स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को तब तक नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि वाद निपटान के लिए लंबित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 के इस रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता ने अपनी दिनांक 27.12.2019 की अंतिम वसीयत को पीछे छोड़ दिया था, वादी इन संपत्तियों के लिए आगे उत्तरदायी है और अंततः स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता की संपत्ति के हिस्से के रूप में विभाजित होने के लिए उत्तरदायी है।

2. वर्तमान वाद में तथ्य यह है कि वादी और प्रतिवादी स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता की संतान हैं। वादी ने विभाजन के लिए उपरोक्त वाद दायर करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता की निर्वसीयत मृत्यु हो गई और वादी स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता की दशा में संपत्तियों और परिसंपत्तियों में अपने 1/3 हिस्से के विभाजन की हकदार है और मांग कर रही है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन के लिए शीर्षक मुकदमे पर इस आधार पर आपत्ति जताई है कि उनके पिता, यानी स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता, उनके निधन से पहले ही दिनांकित 27.12.2019 को अपनी अंतिम वसीयत को निष्पादित कर चुके हैं, जिसमें उनके द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्तियों को वितरित किया गया था। यह भी कहा गया है कि उक्त वसीयत वादी को वाद दायर करने से पहले प्रदान की गई थी और वादी उक्त वसीयत के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी था।

4. प्रतिवादी संख्या 1, वर्तमान आवेदन में, कहता है कि वादी ने दुर्भावनापूर्ण रूप से और जानबूझकर वाद में कुछ संपत्तियों को शामिल नहीं किया है जो पिता द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान खरीदी गई हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार उक्त कार्य दुर्भावनापूर्ण है और यदि इन संपत्तियों को शामिल किए बिना विभाजन को आगे बढ़ाया जाता है, तो इसका परिणाम आंशिक विभाजन होगा और इसलिए यह बनाए रखने योग्य नहीं होगा। उक्त

कथन इस तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है कि स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता ने दिनांकित 27.12.2019 की वसीयत निष्पादित की है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 निवेदन करता है कि उपरोक्त संशोधन पक्षकारों के बीच वर्तमान शीर्षक वाले वाद के निर्णय के लिए आवश्यक है। यह कहा गया है कि मांगे गए संशोधनों से वादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा क्योंकि वाद प्रारंभिक अवस्था में है और मुद्दों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त संपत्तियों को पहले ही लिखित में शामिल किया जा चुका है। उपरोक्त संपत्तियों को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा "पैरा के तहत उत्तर" शीर्षक के तहत दायर लिखित बयान में पहले ही शामिल किया जा चुका है

6. वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सबसे पहले परिसीमा के कारण वर्तमान आवेदन का विरोध किया। यह कहा गया है कि संशोधन के लिए एक आवेदन को उस तारीख पर अनुमति नहीं दी जा सकती है जिस पर समान राहत की मांग करने वाला एक नया वाद परिसीमा द्वारा वर्जित होगा। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज बनाम डीईएसयू, 1997 (41) डीआरजे 8 पर भरोसा किया गया, कार्यकारी भाग निम्नानुसार है*:* -

> *"7.3 मुन्नी लाल बनाम ओआरजीआईसी लिमिटेड, (1996) 1 एससीसी 90 में परिणामिक राहत जिसके लिए वादी हकदार था की मांग किए बिना केवल घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, और फिर भी उसने मांग नहीं की थी। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के परंतुक के तहत सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया था। सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 17 के तहत एक आवेदन अपीलीय न्यायालय*

में दायर किया गया था, जिसमें अभिवचनों में संशोधन करके परिणामी राहत की मांग की गई थी, जिस तारीख से वाद को परिसीमा द्वारा रोक दिया गया था। आवेदन खारिज कर दिया गया था। उनके माननीय न्यायमूर्ति ने अभिनिर्धारित किया

> *"वैकल्पिक राहत के लिए पूछा जाना उपलब्ध था जब वाद दायर किया गया था लेकिन नहीं बनाया गया था। अपीलीय न्यायालय या द्वितीय अपीलीय न्यायालय में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित किए जाने के बाद उसे वाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।*

7.4 इस प्रकार, कानून उचित प्रकार से सुस्थापित है कि उस तारीख को संशोधन के लिए एक वादपत्र पेश करके वाद में राहत जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिस दिन उस राहत की मांग करने वाले वाद को परिसीमा द्वारा रोक दिया जाएगा।

7. साउथ कोंकण डिस्टिलरीज और अन्य बनाम प्रभाकर गजानन नाइक और अन्य (2008) 14 एससीसी 632 के मामले पर भरोसा किया गया है, कार्यकारी भाग निम्नानुसार है: -

> *" 14. उपरोक्त से, इसलिए, अभिवचन में संशोधन के लिए आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में कानून के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि न्यायालय आम तौर पर, एक नियम के रूप में, संशोधन की अनुमति देने से इनकार करते हैं, यदि संशोधित दावे पर एक नया वाद आवेदन दाखिल करने की तिथि पर परिसीमा द्वारा वर्जित होगा। लेकिन यह एक ऐसा कारक होगा जिसे विवेक के प्रयोग में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए, और यदि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक है तो इसे आदेश देने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।*

...

27. हमारे द्वारा किए गए पूर्वोक्त निष्कर्षों और लिखित बयान के संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के विवेक के प्रयोग के मामले में विचारण न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और प्रतिदावे को ध्यान में रखते हुए, लिखित बयान और प्रतिदावे के संशोधन के लिए अपीलार्थीगण की ओर से देरी और कमी अभिवचनों के संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक कारक होगा। जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, अभिवचनों में संशोधन के लिए आवेदन दायर करने में साढ़े तेरह साल की देरी हुई है। इसके अलावा, संशोधन के लिए आवेदन में, अपीलार्थीगण ने इस तरह की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इन परिस्थितियों में, हमें विचारण न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लिखित बयान और प्रतिदावे में संशोधन के लिए प्रार्थना को खारिज करने में विचारण न्यायालय पूरी तरह से न्यायसंगत था।

8. इसके अलावा, वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तावित संशोधनों का इस आधार पर विरोध किया कि संशोधन के आधार पर शामिल की जाने वाली संपत्तियां 1999, 2006 और 2009 के वर्षों में वादी और उसके पति की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं। इसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में स्वीकार करने के लिए कहा गया है जिसमें यह कहा गया है कि पक्षकारों के पिता ने वादी को धन हस्तांतरित किया जिसके माध्यम से इसे प्राप्त किया गया था। इसलिए, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 4

और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के मद्देनजर, वर्तमान आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है चौधरी बनाम अजुधिया, एमएएनयू/एचपी/0100/2001 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का विश्वास किया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू महिला द्वारा अर्जित की गई कोई भी संपत्ति, चाहे वह कितनी भी अर्जित की गई हो, उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाती है और उस पर उसके द्वारा मालिक के रूप में रखी जाएगी। कार्यकारी भाग निम्नानुसार है:-

> *"10. यह ध्यान दिया जा सकता है कि हिंदू महिला के पास मौजूद कोई भी संपत्ति, चाहे वह किसी भी तरह से अर्जित की गई हो, अधिनियम की धारा 14(1) के लागू होने के बाद उसकी पूर्ण संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार, हिंदू महिला की ओर से उसके जीवन पर्यंत भरण-पोषण के लिए दी गई संपत्ति और उस क्षमता में उसके कब्जे के संबंध में प्रतिबंध या सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत, एक महिला बिना किसी परिसीमा के संपत्ति विरासत में पाती है। धारा 14 की उप-धारा (2) उप-धारा (1) का अपवाद है। उप-धारा (1) वहां लागू होती है जहां हिंदू महिला अपने पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता में संपत्ति अर्जित करती है और उस पर कब्जा करती है, जबकि, उप-धारा (2) वहां लागू होती है जहां हिंदू महिला को ऐसी संपत्ति पर किसी भी पहले से मौजूद अधिकार के बिना पहली बार संपत्ति मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय ने वेडेबोयिना तुलासम्मा और अन्य बनाम वेडेबोयिना शेष रेड्डी (मृत) एल.आर. एआईआर 1977 सर्वोच्च न्यायालय 1944 में अधिनियम की धारा 14 (1) और (2) के दायरे की व्याख्या करते हुए, यह पाया गया कि उप-धारा (1) और धारा 14 अपने दायरे में बहुत बड़ी है और इसमें हिंदू महिला द्वारा संपत्ति के हर तरह के अधिग्रहण*

को शामिल किया गया है, जिसमें भरण-पोषण के बदले अधिग्रहण भी शामिल है, चाहे ऐसी संपत्ति अधिनियम के लागू होने की तिथि पर उसके पास थी या बाद में अर्जित या कब्जे में ली गई थी। ऐसी स्थिति में, हिंदू महिला संपत्ति की पूरी मालिक बन जाती है। उपधारा (2), यह टिप्पणी की गई, उपधारा (1) के प्रावधान या अपवाद की प्रकृति की है और चूंकि यह हिंदू समाज में एक महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाकर सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गणना किए गए प्रावधान का अपवाद है, इसलिए इसे सख्ती से इस तरह से व्याख्यायित किया जाना चाहिए कि यह उपधारा (1) में निहित सुधारात्मक प्रावधान के व्यापक दायरे पर यथासंभव कम से कम प्रभाव डाले। माननीय न्यायाधीशों ने आगे टिप्पणी की:

... इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो उपधारा (1) *की प्रभावकारिता को छीन ले और एक हिंदू महिला को उप-धारा* (1) *द्वारा उसे दी जाने वाली सुरक्षा से वंचित करे।*

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

10. अभिवचनों के संशोधन से संबंधित कानून सुस्थापित है, अभिवचनों में संशोधन को कुछ सीमाओं के अधीन उदारतापूर्वक अनुमति दी जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1128 में अपने निर्णय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है*:* -

"70. हमारे अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार अभिव्यक्त किए जा सकते हैं:

i) सि.प्र.स. आदेश II नियम 2 बाद के वाद के खिलाफ एक वर्जन के रूप में कार्य करता है यदि उसके आवेदन के लिए अपेक्षित शर्तें संतुष्ट

हैं और अभिवचन के संशोधन का क्षेत्र इसकी सीमा से बहुत दूर है। इस प्रकार, सि.प्र.स. के आदेश II नियम 2 के तहत संशोधन पर रोक लगाई गई है, यह गलत है और इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है।

ii) सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हैं बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह न हो। यह अनिवार्य है, जैसा कि सि.प्र.स. के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्द्ध भाग में "करेगा " शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।

iii) संशोधन की प्रार्थना की अनुमति दी जाए

i) यदि पक्षकारों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित न्यायनिर्णयन के लिए संशोधन आवश्यक है, और

ii) कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते

(क) संशोधन से दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होता है,

(ख) संशोधन द्वारा, संशोधन की मांग करने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए किसी भी स्पष्ट स्वीकृत को वापस लेने की मांग नहीं करते हैं जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करता है और

(ग) संशोधन एक समय वर्जित दावे को नहीं बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक मूल्यवान अर्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में) को दूसरे पक्ष से छीन लेता है

(iv) संशोधन के लिए एक प्रार्थना को आम तौर पर अनुमति देने की आवश्यकता होती है जब तक कि

(i) संशोधन द्वारा, एक समयबद्ध दावा पेश करने की मांग की जाती है, जिस स्थिति में यह तथ्य कि दावा समय वर्जित होगा, विचार के लिए एक प्रासंगिक कारक बन जाता है,

(ii)संशोधन वाद की प्रकृति को बदलता है,

(iii)संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या

(iv)संशोधन द्वारा, दूसरा पक्ष एक वैध बचाव खो देता है।

(v) अभिवचनों में संशोधन के लिए प्रार्थना से निपटने में, न्यायालय को अतितकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, और आमतौर पर उदार होने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जहां विपरीत पक्ष को लागतों द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है।

(vi) जहां संशोधन से न्यायालय को विवाद पर सटीक विचार करने में सहायता मिलेगी तथा अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता मिलेगी, वहां संशोधन की प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए।

(vii) जहां संशोधन ने कार्यवाही के समयबद्ध कारण को पेश किए बिना केवल एक अतिरिक्त या एक नया दृष्टिकोण पेश करने की मांग की, संशोधन को परिसीमा समाप्त होने के बाद भी अनुमति दी जा सकती है।

(viii) जहां वाद में तात्विक विवरणों की अनुपस्थिति को सुधारने का इरादा हो, वहां संशोधन की अनुमति न्यायोचित रूप से दी जा सकती है।

(ix) केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में विलंब प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां विलंब का पहलू तर्कपूर्ण है, संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और निर्णय के लिए अलग से परिसीमा के मुद्दे को तैयार किया जा सकता है।

(x) जहां संशोधन वाद की प्रकृति या कार्यवाही के कारण को इस तरह से बदलता है कि एक बिल्कुल नया मामला बनता है, जो वाद में स्थापित मामले से अलग है, वहां संशोधन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, जहां संशोधन की मांग केवल वाद में राहत के संबंध में है, और उन तथ्यों पर आधारित है जो वाद में पहले से ही अभिवचन दिए गए हैं, आमतौर पर संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

(xi) जहां विचारण शुरू होने से पहले संशोधन की मांग की जाती है, वहां न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में उदार होना आवश्यक है। न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि विपरीत पक्ष के पास मौका होगा संशोधन में स्थापित मामले को पूरा करें। इस प्रकार, जहां

संशोधन के परिणामस्वरूप विपरीत पार्टी के लिए अपूरणीय पूर्वाग्रह नहीं होता है, या विपरीत पार्टी को एक लाभ से वंचित नहीं किया जाता है, जिसे उसने संशोधन की मांग करने वाला पक्षकार द्वारा प्रवेश के परिणामस्वरूप प्राप्त किया था, संशोधन की अनुमति दी जानी आवश्यक है। समान रूप से, जहां पक्षकारों के बीच विवाद में मुख्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए न्यायालय के लिए संशोधन आवश्यक है, संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। (देखें विजय गुप्ता बनाम गगनिंदर कुमार गांधी, 2022 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 1897)

11. उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब मैं संशोधन के लिए आवेदन के विरोध पर चर्चा करूंगा।

12. विभाजन के लिए एक वाद में प्रत्येक वादी एक प्रतिवादी है और प्रत्येक प्रतिवादी एक वादी है। प्रस्तावित संशोधन, यानी अतिरिक्त तीन संपत्तियों के विभाजन की मांग, पहले से ही अभिवचनों का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि ये प्रतिवादी सं 2 द्वारा दायर लिखित बयान में शामिल हैं। प्रतिवादी सं 2 के लिखित बयान के सम्बंधित पैराग्राफ निम्नानुसार हैं*:* -

"*छ. यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वादी और उसके पति पर लगभग* 22 *करोड़ रुपए का ऋण बकाया है, साथ ही स्वर्गीय श्रीमती उषा गुप्ता की लगभग* 5 *करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसे वादी ने* जवाब देने वाले *प्रतिवादी को छोड़कर हड़प लिया है, जो कि पक्षकारों के पिता स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता की कानूनी संपत्ति के हित में पूरी तरह से वसूलने योग्य है, क्योंकि ये राशियाँ उनके और उनके पति द्वारा उनके पिता से लिए गए ऋण। दहेज। अवैध परितोषण आदि हैं, साथ ही इसमें पक्षकारों की दिवंगत माँ यानी स्वर्गीय श्रीमती उषा गुप्ता की संपत्ति और आभूषण शामिल हैं, जिनकी संपूर्ण संपत्ति वादी द्वारा उनकी मृत्यु के बाद उनके भाइयों*

यानी प्रतिवादी संख्या 1 *और प्रतिवादी संख्या* 2 *के हित के लिए बिना किसी परामर्श या हिस्सेदारी की पेशकश किए तेजी से और चुपके से हड़प ली गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने वादपत्र के पैरा* 3 *में जानबूझकर तीन संपत्तियों को बाहर रखा है, जो उसने अपने दिवंगत पिता की कानूनी संपत्ति से लिए गए ऋणों से अर्जित की हैं और जो उक्त संपत्तियों के विरुद्ध उससे और उसके पति से वसूली योग्य हैं। यह भी उत्तर देने वाले प्रतिवादी के ज्ञान में है कि वादी के पति ने कई मौकों पर अपने मृतक पिता के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाई ताकि वह उससे और वादी के नाम से पैसे ऐंठ सके, जो कानूनी शर्तों के अनुसार दहेज का अपराध होगा।*

.....

<u>पैरा अनुसार उत्तर</u>

...

3. *वादपत्र के पैरा* 3 *की विषय-वस्तु को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि वे कानून और तथ्य की मनमाने ढंग से की गई व्याख्याओं पर आधारित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता की कानूनी संपत्ति का हिस्सा बनने वाली सभी चल और अचल संपत्तियां उनके जीवनकाल के दौरान स्व-अर्जित संपत्तियां थीं और विरासत में नहीं मिली थीं और या किसी* हिन्दू अविभाजित परिवार *का हिस्सा नहीं थीं। विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वादी का वास्तविक उद्देश्य* पक्षकारों *के स्वर्गीय पिता की कानूनी संपत्ति का हिस्सा बनने वाली संपत्तियों का वर्णन करने के संदर्भ में उनके द्वारा किए गए जानबूझकर विलोपन से स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी से तीन संपत्तियों को छोड़ दिया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे उसकी हैं, बिना किसी कानून या तथ्य के आधार के और ऐसी संपत्तियों के लिए धन का स्रोत स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता थे, जिन्होंने वादी और प्रतिवादी संख्या* 1 *दोनों से अपने आईटीआर रिटर्न में 'ऋण' के शीर्षक के तहत किए गए*

भुगतानों से भी निपटा है। परिसंपत्तियों की सही सूची (जिनमें वादी द्वारा जानबूझकर छोड़ी गई परिसंपत्तियां भी शामिल हैं) इस प्रकार दी गई है:

<u>अचल संपत्ति</u>:

<u>दिल्ली</u>:

i. *ए* -8, *ग्रेटर कैलाश* - I, *नई दिल्ली*

ii. *एम*-24, *ग्रेटर कैलाश* - II, *नई दिल्ली*

iii. *एम*-225, *ग्रेटर कैलाश* - II, *नई दिल्ली*

iv. *जी*-14, *हौज खास, नई दिल्ली*

v. (vi) *जीएफ*-04, *चिरंजीवी टावर*, 43, *नेहरू प्लेस, नई दिल्ली*

vi. *ई*8-*ए, प्रथम तल, हौज खास मेन मार्केट, नई दिल्ली*

vii. ***<u>फ्लैट -408, अधिश्वर अपार्टमेंट, 34 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली</u>***

<u>मुंबई</u>:

i) *फ्लैट नंबर*, 215, *मेकर चैंबर* V, *नरीमन पॉइंट, मुंबई*

ii) *शॉप नंबर* 1 *एंड* 2 (*जीएफ*), *रोकड़िया, लैंडमार्क को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, विले पार्ले* (*ई*) *मुंबई*

(iii) ***<u>141, टॉवर ए, कल्पतरु होरीजोन, एस के अहिरे मार्ग, नियर दूरर्शन वर्ली, मुंबई</u>"***

[अज्ञात और छिपी हुई संपत्तियां, निवेशा एफ.डी.,।बीमा और आवर्ती जमा योजनाएं, आदि जो वादी द्वारा स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता से धन को डायवर्ट करके बनाई गई हैं, जिसके लिए उसे अपने नाम पर एफडी सहित खाता होना चाहिए जो स्वर्गीय श्री एम.एल.गुप्ता की संपत्ति से परिवर्तित हैं और जिसे उसने इस माननीय न्यायालय से छुपाया है।

[स्वर्गीय श्रीमती उषा गुप्ता के आभूषण और अन्य चल वस्तुओं को वादी द्वारा जवाब देने वाले प्रतिवादी की सहमति के

बिना हड़प लिया गया और तेजी से हटा दिया गया, जिसकी राशि 5 करोड़ रुपये है (अनुमान के अनुसार)]

इसलिए, वादी ने इस माननीय न्यायालय में निष्ठावान रूप से संपर्क नहीं किया है और अपने मृतक पिता की कानूनी संपत्ति के लिए कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋणों के लिए जवाबदेह होने से बचने का प्रयास किया है। इसके अलावा, प्रतिवादी स.1 और 2 को वंचित करते हुए *वादी को अपने दिवंगत माता, स्वर्गीय श्रीमती उषा गुप्ता के लॉकर से निकाले गए आभूषणों और अन्य संपत्तियों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, साथ ही उनकी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा भी साझा करना चाहिए, जिसे उनके अलावा किसी ने नहीं देखा है। यह विनम्रतापूर्वक, बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्तुत किया जाता है कि वही वादी अपने पिता की अंतिम वसीयत और वसीयतनामे के आधार पर शेष पक्षों के साथ 'पारिवारिक समझौता' करने के लिए तैयार थी, लेकिन प्रतिवादी पर दबाव डालने और उसे जबरन हौज खास स्थित संपत्ति का हिस्सा बेचने के लिए राजी करने में असमर्थ होने के कारण, उसने अब यह रंग-बिरंगा वाद दायर करने का सहारा लिया है, जो बिना किसी कार्यवाही के कारण है।*

13. प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान का अवलोकन करने से पता चलता है कि वर्तमान आवेदन में प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान में सम्मिलित किए जाने वाले संशोधनों को प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान में पहले ही शामिल कर लिया गया है। इसलिए, कोई भी ऐसी भौतिक अनियमितता नहीं है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है। यदि प्रार्थना के अनुसार संशोधन की अनुमति दी जाती है तो वादी को कोई

नुकसान नहीं होगा क्योंकि विभाजन के लिए वाद में दोनों प्रतिवादियों के अभिवचनों को पढ़ना और उनसे निपटना होगा।

14. वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि तीन संपत्तियां अर्थात् (क) फ्लैट -402, अधिश्वर अपार्टमेंट, 34 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली 141, (ख) 141, टॉवर ए, कल्पतरु होराइजन, एसए अहिरे मार्ग, दूरदर्शन वर्ली के पास, मुंबई और (ग) ई 8-ए, पहली मंजिल, हौज खास मेन मार्केट, नई दिल्ली, को समय वर्जित दावों के कारण विभाजन के लिए संपत्तियों के पूल में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वादी द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण 1999, 2006 और 2009 के वर्षों में किया गया था।

15. हालांकि वादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क में कुछ गुणागुण हो सकता है, लेकिन वर्तमान संशोधन आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि संपत्तियों को विभाजन के लिए सामान्य पूल में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे चुनौती देना परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है।

16. ऐसा करके, यह न्यायालय एक प्रतिवादी, यानी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल सि.प्र.स. आदेश VI नियम 17 के तहत एक संशोधन आवेदन का निर्णय करते हुए, निहितार्थ द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान में किए गए कथनों के गुणागुण पर संक्षेप में निर्णय लेगी। इसकी अनुमति नहीं है। यह न्यायालय सि.प्र.स. के आदेश VI नियम 17 के तहत संशोधन के लिए एक आवेदन का निर्णय करते समय प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान में किए

गए कथनों के गुणागुणों का निर्णय प्रतिवादी संख्या 2 को सुने बिना नहीं कर सकती है।

17. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत कुमार बनाम मंगल सेन वधेरा में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है -

> *"16. आम तौर पर संशोधन की अनुमति नहीं है यदि यह कार्यवाही के कारण को बदलता है। लेकिन यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जहां संशोधन कार्यवाही के एक नए हेतुक की वृद्धि किए जाने का माध्यम नहीं बनता है, या एक नया मामला नहीं उठाता है, परंतु यह अभिलेख पर पहले से ही मौजूद तथ्यों में वृद्धि करने से अधिक और कुछ नहीं होता है, संशोधन को वैधानिक अवधि के बाद भी अनुमति दी जाएगी.....*

18. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि उपर्युक्त तीन संपत्तियों के विभाजन के संबंध में कथन प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान में पहले से ही अभिलेख पर हैं, प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान में इसे संशोधित करने / सम्मिलित करने अनुमति दी जानी चाहिए।

19. इसके अलावा, रघु तिलक डी. जॉन बनाम एस रायप्पन और अन्य, (2001) 2 एससीसी 472 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह अभिवचन जो संशोधन के माध्यम से जोड़ी जाने वाली राहत को परिसीमन द्वारा वर्जित किया गया है, विवाद का विषय बनाया जा सकता है और संशोधन को मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अनुमति दी जाएगी। यह निम्नानुसार है: -

"5. चरण दास बनाम अमीर खान [एआईआर 1921 पीसी 50: आईएलआर 48 कैल 110], एल.जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जार्डाइन स्किनर एंड कंपनी [एआईआर 1957 एससी 357: 1957 एससीआर 438], गंगा बाई बनाम विजय कुमार [(1974) 2 एससीसी 393], गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम [(1978) 2 एससीसी 91] और विभिन्न अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का संदर्भित करने के बाद, बी.के. नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई [(2000) 1 एससीसी 712: जेटी (1999) 10 एससी 61] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> *"3. सि.प्र.स. के आदेश 6 नियम 17 का प्रयोजन और उद्देश्य किसी भी पक्ष को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर अपनी अभिवचनों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति देना है जो उचित हो सकते हैं। संशोधन की अनुमति देने की शक्ति व्यापक है और विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर न्याय के हित में कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रयोग किया जा सकता है। यह सत्य है कि संशोधन को अधिकार के मामले के रूप में और सभी परिस्थितियों में दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि न्यायालयों को ऐसी प्रार्थनाओं का निर्णय करते समय अतितकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। उदार दृष्टिकोण सामान्य नियम होना चाहिए, विशेषत: उन मामलों में जहां दूसरे पक्ष को लागतों के साथ क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। कानून की तकनीकी बारीकियों को पक्षों के बीच न्याय के प्रशासन में न्यायालयों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी जाती है।*

6. यदि उपरोक्त परीक्षण को तत्काल मामले में लागू किया जाता है, तो मांगे गए संशोधन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। संशोधन की अनुमति देने का प्रमुख उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना है। यह अभिवचन कि संशोधन के माध्यम से मांगी गई राहत को समय के साथ रोक दिया गया था, मामले की परिस्थितियों में बहस योग्य है, जैसा कि वाद के पैरा 8(क) से 8(च) में किए गए कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है, जिन्हें संशोधन के माध्यम से शामिल करने की मांग की गई थी। हमें लगता है कि मामले की परिस्थितियों में विवादित होने की अभिवचन को संशोधन की अनुमति देने के बाद मुद्दे का विषय बनाया जा सकता है।

20. वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस आधार पर प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया कि ये बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से प्रभावित हैं।

21. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि संपत्ति, यानी एम -225, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, जिसे वादी द्वारा विभाजित करने की मांग की गई है, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर है। इसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 1995 में एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था। यदि प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर वादी से संबंधित संपत्तियों को विभजित करने की मांग को बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा अड़चन पड़ती है और उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है तो यह वादी पर निर्भर नहीं करता है कि वह प्रतिवादी संख्या 1, यानी एम-225, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली से

संबंधित संपत्ति को शामिल करे। मुझे प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुति में गुणागुण मिलता है और उसी सादृश्य पर, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 की संपत्ति विभाजित की जाने वाली संपत्तियों का हिस्सा है, इसलिए वादी के नाम पर रखी तीन संपत्तियों को सम्मिलित करने से इस स्तर पर बाहर नहीं किया जा सकता है।

22. मुझे प्रतिवादी स. 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण में भी बल मिलता है कि इसके अतिरिक्त सम्मिलित की जाने वाली संपत्तियों को तब खरीदा गया था जब बेटी, यानी वादी, अविवाहित थी, इसलिए बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 4 के तहत रोक लागू नहीं होगी क्योंकि लेनदेन बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के पूर्व-संशोधन थे।.

23. लिखित बयान के संशोधन के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने के इस स्तर पर न्यायालय को प्रस्तावित संशोधन के गुणागुणों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कानून में यह स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालयों को अभिवचनों के संशोधन के संबंध में उदार होना चाहिए, विशेषकर तब जब वादपत्र की तुलना में लिखित कथन में संशोधन की मांग की जाती है। सुशील कुमार जैन बनाम मनोज कुमार, (2009) 14 एससीसी 38 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विश्वास किया गया है यह निम्नानुसार है:-

"13. इस स्तर पर, हम खुद को याद दिला सकते हैं कि कानून अब सुस्थापित है कि एक वादपत्र का संशोधन और एक लिखित बयान का संशोधन जरूरी नहीं कि एक ही सिद्धांत द्वारा नियमित हो।

"15. रक्षा का एक नया आधार जोड़ना या रक्षा को प्रतिस्थापित करना या बदलना कार्यवाही के एक नए हेतुक को जोड़ने, बदलने या प्रतिस्थापित करने के समान समस्या नहीं उठाता है।

(देखें बलदेव सिंह बनाम मनोहर सिंह [(2006) 6 एससीसी 498: एआईआर 2006 एससी 2832], एससीसी पेज. 504, पैरा 15.) इसी तरह का विचार उषा बालासाहेब स्वामी बनाम किरण अप्पासो स्वामी [(2007) 5 एससीसी 602: एआईआर 2007 एससी 1663] में भी व्यक्त किया गया है।

14. यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि (एससीसी पेज. 609, पैरा 22) एक लिखित बयान के संशोधन के मामले में,

"न्यायालय एक वाद की तुलना में अनुमति देने में अधिक उदार होंगी क्योंकि पूर्वाग्रह का प्रश्न बाद की तुलना में पूर्व में बहुत कम होगा और बचाव के एक नए आधार को जोड़ने या बचाव को बदलने या परिवर्तन या लिखित बयान में असंगत अभिवचन लेने की भी अनुमति दी जा सकती है"।

24. पुनरावृत्ति की कीमत पर, जिन तीन संपत्तियों को सम्मिलित करने की मांग की गई है, वे पहले से ही अभिलेख पर हैं और प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान में सम्मिलित हैं। न्यायालय बाद के चरण में तीन संपत्तियों के संबंध में पक्षकारों द्वारा उठाए गए आधारों पर एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार कर सकती है और पक्षकारों को सुनने के बाद इस पर निर्णय कर सकती है।

25. इसके अतिरिक्त, साउथ कोंकण डिस्टिलरीज में वादी द्वारा भरोसा किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय ने (पूर्वोक्त) के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि अभिवचनों के संशोधनों को अनुमति / अस्वीकृत करना विवेकाधिकार का प्रयोग है, यदि न्याय के हित में अपेक्षित हो। उस मामले में यह देखा गया कि साढ़े तेरह वर्ष बाद संशोधन की मांग की गई थी और मामले के तथ्यों में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। वर्तमान मामले में, संशोधन के लिए आवेदन प्रारंभिक अवस्था में दाखिल किया गया है, मुद्दों को अभी तैयार किया जाना है और कोई असाधारण विलंब नहीं हुआ है। उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। सुशील कुमार जैन *(पूर्वोक्त)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कार्यवाही में इसी तरह के चरण में संशोधन आवेदन की अनुमति दी थी। यह निम्नानुसार है*:* -

> *"20. पूर्वोक्त निर्णय और स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है, दस्तावेज अभी तक दायर नहीं किए गए हैं, सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए हैं, हमारा विचार है कि आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.स. के प्रावधान में आवेदन का कोई तरीका नहीं है क्योंकि परीक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।*

26. इसके अतिरिक्त, लुमैक्स (पूर्वोक्त) का निर्णय भी अलग-अलग है क्योंकि उक्त मामले में वादपत्र में संशोधन की मांग की गई थी और न्यायालय ने देखा कि वादी वाद में मांगी गई राहत को बदलने का प्रयास कर रहा है।

जैसा कि पहले ही देखा गया है, वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है, प्रस्तावित संशोधन पहले से ही अभिवचनों यानी प्रतिवादी संख्या 2 का लिखित बयान का हिस्सा हैं।

27. उक्त कारणों से, प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान में संशोधन की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है।

28. संशोधित लिखित बयान आज से दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।

29. वादी उसके बाद चार सप्ताह के भीतर संशोधित लिखित बयान के प्रतिकृति में अपनी सभी आपत्तियों/अभिवचनों को उठाने के लिए स्वतंत्र है।

सि.वा.(मू.प.) 289/2022 और अं.आ. 7971/2022, अं.आ. 7972/2022, अं.आ. 7973/2022, अं.आ. 7974/2022, अं.आ. 7975/2022, अं.आ. 7976/2022, अं.आ. 9506/2022, अं.आ. 13967/2022, अं.आ. 19558/2022, अं.आ. 19559/2022, अं.आ. 16052/2023, अं.आ. 24643/2023, अं.आ. 24644/2023

30. दिनांक 30.05.2024 को संयुक्त निबंधक के समक्ष सूची प्रस्तुत की जाए।

न्या. जसमीत सिंह,

मई 10वीं, 2024/डीजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*